

सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली नरिणय

चर्चा में क्यों?

भारत के सुप्रीम कोर्ट का नरिणय आम कानून व्यवस्था में न्याय देने के लिये आधार का कार्य करने के साथ ही, एक उदाहरण स्थापति करने का भी कार्य करता है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दलिली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मामले और धारा 377 पर दिये गए फैसले को नसिंसंदेह इतिहास में ऐतिहासिक नरिणय के रूप में गनिा जाएगा और यह भवषिय के कई मामलों को प्रभावति भी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख प्रगतशील नरिणय

- मेनका गांधी मामले ने 1970 के दशक के अंत में कानूनी न्यायशास्त्र में बदलाव का जकिर कयिा, जसिमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिक सक्रिय भूमिका नभिर्ई और आपातकाल के बाद अपनी वैधता पर ज़ोर देने की कोशशि की।

मेनका गांधी बनाम संघ 1978

- वर्ष 1977 में मेनका गांधी (वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री) का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लयिा गया था।
- इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
- हालाँकि, कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया।
- यह नरिणय सात न्यायाधीशीय खंडपीठ द्वारा कयिा गया, जसिमें इस खंडपीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में नहिति व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया गया, जसिसे यह फैसला मौलिक अधिकारों से संबंधति मामलों के लिये एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण बना।

केशवानंद भारती मामला 1973

- वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दयिा था कि भारत में संसद नहीं बलक संविधान सर्वोच्च है।
- साथ ही, न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिये संविधान के मौलिक ढाँचे के सिद्धांत को भी पारति कर दयिा। इसमें कहा गया कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढाँचे को प्रतिकूल ढंग से प्रभावति करता हो।
- न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा कयिे गए संशोधन की जाँच संविधान के मूल ढाँचे के आलोक में करने के लिये स्वतंत्र है।
- इसी तरह, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संसद को अपनी 'मूल संरचना' को बदलने से रोका, जो भारतीय राज्य को अपने कई दक्षिण एशियाई समकक्षों (चाहे अधिनियकवादी शासन हो या अन्य अतिरिक्त संविधानिक माध्यमों से) के समान गरिने से बचाने के लिये व्यापक रूप से जाना जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट एक अभलिखीय अदालत होगी और इस तरह की अदालत को सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जसिमें स्वयं की अवमानना के लिये दंडति करने की शक्ति भी शामिल है।
- अभलिख न्यायालय से आशय उस उच्च न्यायालय से है, जसिके 'नरिणय' सदा के लिये लेखबद्ध होते हैं और जसिके अभलिखों का प्रमाणति मूल्य होता है।
- उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों और नचिली अदालतों में प्रक्रयिात्मक मुद्दों से नपिटने के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरिधारति उदाहरण महत्त्वपूर्ण हैं।

